नव-स्वदेशी

भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भरता को पुनर्परिभाषित करना

1. प्रस्तावना: एक राष्ट्रीय लोकाचार का विकास

"स्वदेशी" की अवधारणा भारतीय चेतना में एक पवित्र स्थान रखती है। ऐतिहासिक रूप से, यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में—विशेष रूप से 1905 के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान—स्वदेशी लचीलेपन के पक्ष में विदेशी निर्भरता के बहिष्कार के आह्वान के साथ राजनीतिक प्रतिरोध के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा। यह आवश्यकता से पैदा हुआ एक दर्शन था, जिसका उद्देश्य औपनिवेशिक शासन की आर्थिक मशीनरी को पंगु बनाना था।

हालांकि, जैसे-जैसे भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने और अंततः 2047 तक एक विकसित राष्ट्र (**विकसित भारत**) बनने की ओर अग्रसर है, स्वदेशी की परिभाषा एक गहरे वैचारिक बदलाव (Paradigm Shift) से गुजर रही है। अब हम "बहिष्कार" के युग से आगे निकलकर "निर्माण" के युग में प्रवेश कर चुके हैं। यह "नव-स्वदेशी" आंदोलन अलगाववाद या पूर्व-औद्योगिक तरीकों की ओर वापसी नहीं है। इसके बजाय, यह भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (Global Value Chains) में एक प्रमुख और आत्मनिर्भर खिलाड़ी के रूप में एकीकृत करने की एक परिष्कृत आर्थिक रणनीति है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत, स्वदेशी को "मेक इन इंडिया" और "वोकल फॉर लोकल" के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है, जो राष्ट्र को उपभोग-आधारित विकास से उत्पादन-आधारित संप्रभुता की ओर ले जा रहा है।

2. नव-स्वदेशी का दर्शन: चार मुख्य स्तंभ

नव-स्वदेशी एक व्यावहारिक और विकास-समर्थक ढांचा है जो राष्ट्रीय पहचान को आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ जोड़ता है। यह चार समकालीन स्तंभों पर आधारित है:

I. तकनीकी संप्रभुता (Technological Sovereignty)

डिजिटल युग में, आत्मनिर्भरता अब केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है; यह डेटा और कोड के बारे में भी है। तकनीकी संप्रभुता का अर्थ है डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना और सीमा पार के जोखिमों के प्रबंधन के लिए स्वदेशी तकनीकी समाधान तैयार करना। इसमें डेटा भंडारण का स्थानीयकरण, स्वदेशी 5G उपकरणों का विकास और भारतीय ऐप्स एवं प्लेटफार्मों को अपनाना शामिल है। विदेशी तकनीकी प्रणालियों पर निर्भरता कम करके भारत यह सुनिश्चित करता है कि उसका डिजिटल ढांचा भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव के खिलाफ सुरक्षित रहे।

II. भू-राजनीतिक स्वायत्तता (Geopolitical Autonomy)

आर्थिक लचीलापन कूटनीति का सबसे बड़ा साधन है। एक राष्ट्र जो अपनी बुनियादी जरूरतों—ऊर्जा, रक्षा और भोजन—के लिए दूसरों पर निर्भर है, उसे मजबूर किया जा सकता है। नव-स्वदेशी का लक्ष्य आर्थिक शक्ति का उपयोग वैश्विक तनावों के बीच रास्ता बनाने, तेल आयात में विविधता लाने, रक्षा घटकों के स्थानीयकरण और एक मजबूत घरेलू वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर विदेशी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए करना है।

III. स्थिरता और स्थानीय संसाधन (Sustainability and Local Resources)

आधुनिक स्वदेशी स्वाभाविक रूप से वैश्विक ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) मानकों के अनुरूप है। खादी और जैविक कृषि को बढ़ावा देने में एक शक्तिशाली पुनरुत्थान देखा जा रहा है, जो आर्थिक विकास को स्थायी प्रथाओं के साथ जोड़ता है। यह स्तंभ स्वीकार करता है कि विकेंद्रीकृत उत्पादन—जैसा कि मूल रूप से महात्मा गांधी ने परिकल्पना की थी—लंबी दूरी के लॉजिस्टिक्स से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम कर देता है, जिससे "स्थानीय" (Local) शब्द "स्थायी" (Sustainable) का पर्याय बन जाता है।

IV. "वोकल फॉर लोकल" से "वोकल फॉर ग्लोबल"

नव-स्वदेशी का अंतिम लक्ष्य भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह आंदोलन नागरिकों से स्वदेशी और MSME द्वारा निर्मित उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह करता है, न कि केवल दान की भावना से, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उत्पाद गुणवत्ता, लागत और नवाचार के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। इसका लक्ष्य "वोकल फॉर ग्लोबल" है—यानी स्थानीय ब्रांडों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बनाना।

3. आर्थिक आधारशिला: MSME परिदृश्य

इस आर्थिक पुनर्जागरण के केंद्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र है। अक्सर "भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़" कहा जाने वाला MSME क्षेत्र, **आत्मनिर्भर भारत** के व्यापक दृष्टिकोण को सूक्ष्म-आर्थिक वास्तविकता में बदलने का प्राथमिक माध्यम है।

क. आर्थिक प्रभाव का आकलन

आंकड़े एक ऐसे क्षेत्र को प्रकट करते हैं जो न केवल अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, बल्कि कई मायनों में स्वयं अर्थव्यवस्था ही है।

- **जीडीपी और उत्पादन:** भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में MSMEs का योगदान लगभग 30% है और कुल विनिर्माण उत्पादन में लगभग 36% है।
- **निर्यात प्रभुत्व:** "ग्लोबल स्वदेशी" का सबसे मजबूत संकेतक निर्यात की मात्रा है; भारत के कुल निर्यात में MSMEs का योगदान 45% से 48% के बीच है। यह दर्शाता है कि भारतीय छोटे व्यवसाय पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं।

ख. स्वदेशी की मानवीय पूंजी

स्वदेशी मौलिक रूप से स्वदेशी कार्यबल को रोजगार देने के बारे में है। MSME क्षेत्र अनुमानित 11 करोड़ से 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जिससे यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बन गया है। पूंजी-प्रधान भारी उद्योगों के विपरीत, MSMEs में उच्च "रोजगार लोच" (Employment Elasticity) होती है, जिसका अर्थ है कि वे निवेश की गई पूंजी की प्रति इकाई के बदले कहीं अधिक नौकरियां पैदा करते हैं। यह भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है।

ग. समावेशी विकास और धन का लोकतंत्रीकरण

MSME क्षेत्र सामाजिक समानता के साधन के रूप में कार्य करता है। इनमें से 50% से अधिक उद्यम ग्रामीण भारत में स्थित हैं, जो महानगरों की ओर पलायन को रोकते हैं और टियर-2 तथा टियर-3 शहरों में स्थानीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करते हैं। इसके अलावा, सभी MSME इकाइयों में से लगभग 66% के मालिक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों (SC/ST/OBC) से हैं। लैंगिक समानता भी एक प्राथमिकता है, जिसमें 'महिला कॉयर योजना' और PMEGP जैसी पहल के माध्यम से 2030 तक महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

4. उपभोग पैटर्न में बदलाव

नव-स्वदेशी जितना एक आर्थिक आंदोलन है, उतना ही एक मनोवैज्ञानिक आंदोलन भी है। यह "उपभोक्ता नृजातिवाद" (Consumer Ethnocentrism) नामक घटना द्वारा संचालित है, जहाँ उपभोक्ता अब राजनीतिक बहिष्कार के बजाय गुणवत्ता और गौरव के आधार पर स्थानीय उत्पादों को चुन रहा है।

- **वेलनेस और जीवनशैली:** स्थानीय रूप से निर्मित आयुर्वेदिक और वेलनेस उत्पादों को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। उपभोक्ता खादी और हथकरघा जैसे पारंपरिक, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ रहे हैं।
- **डिजिटल स्वदेशी:** भारतीय उपभोक्ता तेजी से भारतीय-विकसित तकनीकी समाधानों को प्राथमिकता दे रहा है। UPI की सफलता से लेकर 'जोहो' (Zoho) जैसी सॉफ्टवेयर कंपनियों के उदय तक, "डिजिटल स्वदेशी" आंदोलन पूरी तरह से सक्रिय है।

5. संरचनात्मक सुधार: "बौनेपन" से "वैश्विक दिग्गजों" तक

दशकों से, भारतीय MSMEs "बौनेपन" (Dwarfism) की घटना से बाधित थे—ऐसी फर्में जो अपनी पसंद से नहीं, बल्कि नियामक घर्षण, संसाधनों की कमी और सीमित बाजार पहुंच के कारण छोटी बनी रहीं। नव-स्वदेशी इन बाधाओं को दूर करने के लिए कई क्रांतिकारी सुधार करता है।

क. डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI)

वाणिज्य का डिजिटलीकरण इस क्षेत्र का सबसे क्रांतिकारी सुधार है। जिस तरह UPI ने भुगतान का लोकतंत्रीकरण किया, **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)** ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण कर रहा है। यह बड़े प्लेटफॉर्मों के एकाधिकार को तोड़ता है, जिससे छोटे कारीगरों और स्थानीय दुकानों को बिना भारी कमीशन दिए वैश्विक खरीदारों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसी तरह, **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM)** ने MSMEs से सार्वजनिक खरीद को अनिवार्य कर दिया है।

ख. ऋण की समस्या का समाधान

ऋण तक पहुंच ऐतिहासिक रूप से MSME क्षेत्र की कमजोरी रही है। **उद्यम पंजीकरण पोर्टल** ने लाखों अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाया है, जिससे वे बैंकों की नजर में आए हैं। इसे **RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance)** योजना द्वारा और मजबूत किया गया है, जो केवल ऋण पर नहीं बल्कि प्रदर्शन-आधारित क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित करती है।

ग. गुणवत्ता ही नई मुद्रा है

"कम लागत, कम गुणवत्ता" के कलंक को दूर करने के लिए सरकार ने **ZED (जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट)** प्रमाणन योजना शुरू की। यह MSMEs को "जीरो डिफेक्ट" (विश्व स्तरीय गुणवत्ता) और "जीरो इफेक्ट" (स्थायी पर्यावरणीय अनुपालन) के साथ सामान बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

घ. वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकरण

अंतिम संरचनात्मक बदलाव तैयार उत्पादों को बेचने के बजाय उच्च-मूल्य वाले घटकों (Components) को बेचने की ओर है। **प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI)** योजनाओं के माध्यम से, सरकार बड़े निर्माताओं को स्थानीय MSMEs से पुर्जे खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यह "हब एंड स्पोक" मॉडल छोटी भारतीय फर्मों को वैश्विक उद्योगों के लिए आवश्यक सहायक इकाइयों में बदलने में मदद कर रहा है।

6. आगे की राह: एक समन्वित राष्ट्रीय प्रयास

नव-स्वदेशी की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए तीन समन्वित कार्रवाइयां होनी चाहिए:

1. **सरकारी निरंतरता:** राज्य को नीतिगत निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार करने की आसानी (Ease of doing business) में सुधार जारी रहे और "इंस्पेक्टर राज" को डिजिटल पारदर्शिता से बदल दिया जाए।
2. **कॉर्पोरेट तालमेल:** बड़े भारतीय कॉर्पोरेट्स को MSMEs को केवल कम लागत वाले वेंडर के बजाय रणनीतिक दीर्घकालिक भागीदारों के रूप में देखना चाहिए। यह तालमेल आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक है।
3. **उपभोक्ता चेतना:** उपभोक्ताओं को "मेड इन इंडिया" उत्पादों को केवल कर्तव्य समझकर नहीं, बल्कि गुणवत्ता पर गर्व के कारण चुनना चाहिए। "मेड इन इंडिया" उत्पाद की हर खरीद राष्ट्र की संप्रभुता में एक सीधा निवेश है।

7. निष्कर्ष: एक आत्मनिर्भर भविष्य की अनिवार्यता

"स्वदेशी" की यात्रा एक पूर्ण चक्र पूरा कर चुकी है। जो एक सदी पहले औपनिवेशिक निर्भरता के खिलाफ एक राजनीतिक बयान के रूप में शुरू हुआ था, वह वैश्विक प्रभुत्व के लिए एक परिष्कृत आर्थिक रणनीति में विकसित हो गया है। जैसे-जैसे भारत **अमृत काल** में आगे बढ़ रहा है, MSME क्षेत्र एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है।

जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने परिकल्पना की है, इस क्षेत्र में भारत को उपभोग के बाजार से उत्पादन के वैश्विक केंद्र में बदलने की क्षमता है। नव-स्वदेशी आंदोलन की सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि हमने कितने उत्पादों का आयात बंद किया, बल्कि इस बात से मापी जाएगी कि दुनिया भारत के कितने उत्पादों के बिना नहीं रह सकती। MSME को सशक्त बनाकर, हम केवल व्यवसाय नहीं बना रहे हैं; हम एक लचीला, संप्रभु और समृद्ध राष्ट्र बना रहे हैं। नव-स्वदेशी एक ऐसे भविष्य का रोडमैप है जहाँ भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल एक भागीदार नहीं, बल्कि इसके मानकों को परिभाषित करने वाला नेता होगा।